Effect of Supreme Court Judgement on Mandal Commission

667. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have had under consideration the question of doing away with the adverse effects of the Supreme Court Judgement with regard to Mandal Commission Report, in so far as it impinges on (i) the quota of reservation of promotion posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Government departments and undertakings and (ii) reservations in respect of Technical and Research posts and specialities, and

(b) if so, what decision has been taken in the matter and what steps have been taken in this regard?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) and (b) The matter under consideration.

गुजरात में मानसिक रूप से अविकिसित व्यक्तियों के लिए कल्याण योजनाएं

668. **श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों तथा 18 वर्ष से कम आयु के मानसिक रूप से अविकसित बच्चों की पृथक-पृथक संख्या कितनी हैं;

(ख) इन बच्चों के कल्याणार्थ सरकार द्वारा लागू की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक इन बच्चों के कल्याणार्थ राज्य सरकार को कितनी सहायता प्रदान की गई और यह सहायता किस रूप में दी गई ;

(घ) क्या राज्य सरकार द्वारा इन कल्याण योजनाओं का पूरा-पूरा लाभ इन बच्चों को दिया जा रहा है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(छ) सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा इस वर्ग को इन योजनाओं का पूरा-पूरा लाभ पहुंचाने के लिये जो विशेष प्रयास किये जा रहे हैं उनका ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम) केसरी: (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने 0–14 वर्ष के आयु वर्ग में बच्चों के विकास में विलंब पर 1991 में देशव्यापी प्रतिदर्श सर्वेक्षण चलाया था। उन बच्चों के आंकड़े जिनमें वय के अन्य बच्चों की तुलना में विकास धीमा और पिछड़ा बताया गया है, गुजरात में ग्रामीण क्षेत्र में विकास में विलंब की दर प्रति हजार 15 तथा शहरी बच्चों में प्रति हजार 25 दिखाया गया है।

(ख) मानसिक मंदता से विकलांग व्यक्तियों की पहचान, शीघ्र कार्रवाई, विशेष शिक्षा और पुनर्वास के लिये निम्नलिखित योजनायें शुरू की गई हैं:–

(1) विकलांगों के पुनर्वास के लिये स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना।

(2) मानसिक मन्दता तथा प्रमस्तिष्काघात वाले व्यक्तियों हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता।

(3) विशेष विद्यालयों को स्थापना के लिये स्वैच्छिक संगठनों को सहायता।

(4) इसके अलावा मानसिक विकलांगों के लिये एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया गया है जो मानव शक्ति विकास, सेवा मोडयूल आदि उपलब्ध करायेगा।

(ग) मंत्रालय द्वारा स्वैच्छिक संगठनों को सीधे सहायता दी जाती है, राज्य सरकारों को नहीं ।

(घ) से (च) उक्त योजना के तहत पुनर्वास सुविधायें प्रदान करने के लिये दी गई सहायता से गुजरात राज्य में 17 गैर सरकारी संगठन कार्य कर रहे हैं ।

(छ) योजनाओं का विस्तृत प्रचार किया जा रहा है तथा गैर सरकारी संगठनों को अनुदान के लिये आवेदन भेजने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है । ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय समर्थन 90% से बढ़ाकर 95 % कर दिया गया है । इसके परिणामस्वरूप स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की राशि 1992–93 के 6.80 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1993–94 में 10.40 करोड़ रुपये हो गया है । गैर सरकारी संगठनों की संख्या भी 1992–93 के 302 से बढ़कर 1993–94 में 315 हो गई है ।

Newspaper Report on Child Prostitutes

669. SHRI VIREN J SHAH: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a report published in the Hindustan Times of October 5, 1994 under the heading, "India has four lakh child prostitutes;"

(b) if so, what are the facts in this regard and what is their number, State-wise; and

(c) what steps Government have taken or propose to take to save the lives of unfortunate and helpless children from sex exploitation?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) Yes, Sir.

(b) There is no scientific data available about the number of Child Prostitutes in India and its pervasiveness. However, the Government is very concerned about this phenomenon and feels that the problem of child prostitution is linked to the general problem of prostitution in the society.

(c) The Government of India has set up a Central Advisory Committee to frame recommendation/plan of action for both legal and non-legal approaches for the rescue and rehabilitation of child prostitutes. The recommendations of the Committee have been sent to the concerned Central Ministries/Departments and to the State Governments for taking appropriate action.

Many of the State Governments have set up State Advisory Committees within their jurisdiction for suggesting measures for the care protection, treatment and rehabilitation of the Young victims rescued from brothel houses.

The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 supplemented by the Indian Penal Code prohibits trafficking in human beings including children. Higher penalties, punishments have been prescribed in cases relating to the prostitution of a child or a minor, under the Act. The Juveniles Justice Act, 1986 provides for the care protection, treatment and rehabilitation of neglected or delinquent juveniles including girls.

The enforcement of the Acts is the responsibility of the State Governments. The Central Government have issued instructions from time to time to all States/Union Territories for strict implementation of the Act. Meetings with DGPs of all the States have been held in this regard.

The Government has an extensive network of Short Stay Home set up under the Juvenile Justice Act for protection and rehabilitation of the victims The services of qualified doctors, psychiatrists are available in the Short Stay Homes. These services are available on part time basis in the Homes under Juvenile Justice Act.

A National Plan of Action for the SAARC Decade (1991—2000 AD) of the girl child focussing on survival, protection and development of the girl child has been formulated. A special set of interventions for adolescent girls has